

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में उद्योगों की भूमिका Role of Industries in Implementation of National Education Policy 2020

डॉ. सुमन रानी

Dr. Suman Rani

Saini Institute of Girls Education, Rohtak
suman7242176@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21817843>

सारांश

भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) को अनुमोदित किया गया जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक एवं समग्र सुधार सुनिश्चित करना है। यह स्वाधीन भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में लागू की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य उद्देश्यों में से एक मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी में उद्योग व तकनीकी की दृष्टि से सशक्त बनाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य शिक्षा को बहुविषयक, रोजगारोन्मुख, कौशल आधारित और लचीला बनाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति में उद्योगों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि वे शिक्षा व रोजगार के बीच की दूरी को कम करने का कार्य करते हैं जिससे उद्योग विशेषज्ञ विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम को रोजगार केन्द्रित बनाने में मदद कर सकते हैं तथा स्टार्टअप एवं उद्यमिता में वित्तपोषण विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प पूरा किया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों को केवल अकादमिक ज्ञान देने की बजाय उन्हें उद्योग-उन्मुख तथा रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। प्रस्तुत शोध पत्र में शैक्षिक क्षेत्र में उद्योगों की भूमिका, सहभागिता, चुनौतियों एवं संभावनाओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

Abstract

The Government of India implemented the National Education Policy (NEP) 2020 on 29th July 2020. This is the third education policy of independent India. The first education policy was implemented in 1968. One of the main objectives of the National Education Policy is to strengthen the Indian education system in the 21st century from the perspective of industry and technology. The objective of NEP 2020 is to make education multidisciplinary, employment-oriented, skill-based, and flexible. In achieving this goal, the role of industries is extremely important because they work to reduce the gap between education and employment. This helps industries design employment-centered curricula for specialized students and fulfill the commitment of making students self-relevant in startups and entrepreneurship. The aim of NEP is not just to provide academic knowledge to students but to provide them opportunities in industry-oriented sectors and employment, thus making them self-dependent. The present research paper presents a detailed analysis of the role of industries in the academic field, their participation, challenges, and possibilities.

मुख्यशब्द: डिजिटल युग, प्रशिक्षु, समावेशी शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, स्टार्टअप, सृजनात्मक।

Key words: Digital Era, Trainee, Inclusive Education, Skill Development, Startup, Creativity

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को भूमंडलीकरण स्तर पर खरा उतारना है। चूंकि शैक्षिक पाठ्यक्रम में 21वीं सदी की परिस्थितियों के अनुकूल छात्रों को व्यावहारिक और तकनीकी प्रशिक्षण को महत्व दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव का एक नया दौर है क्योंकि आधुनिक युग तकनीकी प्रशिक्षण, हथकरघा रोजगार, डिजिटल क्रांति, इंटरनेट, अप्रेंटिसशिप, स्टार्टअप और उद्यमिता, कौशल युक्त पाठ्यक्रम, करके सीखना वैश्विक प्रतिस्पर्धा एवं सांस्कृतिक रूप से प्रौद्योगिकी युग में छात्रों को केवल उपाधि नहीं, बल्कि रोजगारोन्मुख संबंध प्रायोगिक कौशल की आवश्यकता है। भारत में युवा कौशल दिवस की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी।

भारत में शैक्षणिक चुनौतियों पर विचार करके शिक्षा के सुधार हेतु विभिन्न समयों में भारत द्वारा विभिन्न आयोगों की नियुक्तियाँ हुई हैं। स्वतंत्रता से पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय शिक्षा व्यवस्था के विभिन्न पक्षों एवं समस्याओं के अध्ययन हेतु समय-समय पर अनेक शिक्षा आयोगों एवं समितियों का गठन किया गया। इन आयोगों ने शिक्षा के विविध क्षेत्रों का गहन अध्ययन कर सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत किये। सरकार ने इनकी अनेक महत्वपूर्ण संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक सुधार किये, किन्तु वित्तीय, प्रशासनिक, सामाजिक तथा व्यावहारिक सीमाओं के कारण किसी भी आयोग की सभी संस्तुतियों को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सका। कोठारी आयोग (1964-1966) प्रथम आयोग है जिसने शिक्षा के सभी स्तरों एवं समस्याओं पर समग्र रूप से दृष्टिपात किया और पहली बार विचार करके शिक्षा का व्यवसायीकरण करने हेतु बहुमूल्य सुझाव दिए। कोठारी कमीशन के अनुसार —“ज्ञान देकर उसका उपयोग व सिखाकर कार्य एवं उपयोग करके ज्ञान देना अत्यन्त उपयुक्त है। इससे बालक अवलोकन करके, प्रयोग

कार्य करके ज्ञान प्राप्त करेंगे।”¹ इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर आयोग की यह सिफारिश थी कि शिक्षा का उद्देश्य समान और अर्थव्यवस्थाओं के अनुरूप होना चाहिए। विशेष तौर पर भारत जैसे विकासशील देश में उद्योगों व शिक्षा के बीच तालमेल स्थापित कर कौशल आधारित शिक्षा प्रणाली तैयार करनी चाहिए जिससे आने वाले समय का युवा आत्मनिर्भर बन सके।

समाज सुधारक रविन्द्र नाथ टैगोर ने भी उस समय शिक्षा व उद्योग के संबंध में कहा कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह व्यावहारिक ज्ञान रचनात्मक और समाज के साथ-साथ सामंजस्य स्थापित करने वाली होनी चाहिए। रविन्द्र नाथ टैगोर के अनुसार— “ज्ञान का उद्देश्य विद्या का आडम्बर नहीं बल्कि विवेक की प्राप्ति है..... इसका अर्थ सामान्य जीवन का पाठ नहीं, बल्कि सृजनात्मक जीवन का पाठ है। क्योंकि जीवन चाहे जितना जटिल हो जाए, अगर उसके केन्द्र में एक जीवंत व्यक्तित्व है तो उसके सृजन भी एकता अक्षुण्ण रहेगी, अपना भार यह खुद पूर्ण गरिमा में साथ वहन कर लेगा”²। अतः स्वतंत्रता पूर्व भी व्यावसायिक शिक्षा को विद्यार्थियों की समग्र शैक्षिक प्रक्रिया में शामिल कर उनकी व्यावसायिक और व्यक्तिगत दक्षता का विकास पर बल दिया गया।

उद्योगों की भूमिका का महत्व

1. व्यावसायिक शिक्षा की सहभागिता — (Vocational Education) NEP 2020 के अनुसार, स्कूली शिक्षा से ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम सुलभ कराने की योजना है।

कौशल प्रशिक्षण प्रशिक्षुता के माध्यम से विद्यार्थियों को किसी कंपनी द्वारा एक प्रशिक्षु के रूप में चयनित किया जाता है तथा उसे कक्षा आधारित (सैद्धान्तिक) और कार्य स्थल आधारित (व्यावहारिक) प्रशिक्षण दिया जाता है। यह कार्यक्रम छात्रों के विभिन्न फ़ैसलों को प्रशिक्षित करता है। जिससे वे एक कुशल कार्यकारिणी का हिस्सा बन सकें और योग्यतानुसार बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकें। भारत में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

जैसी संस्थाएँ औद्योगिक शैक्षिक कार्यक्रम को बढ़ावा देती हैं। “राष्ट्रीय कौशल विकास निगम भारत सरकार द्वारा स्थापित एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनशिप (PPP) संस्था है, जिसका प्रमुख उद्देश्य देश के कौशल विकास को बढ़ावा देना है।”⁴

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) की प्रमुख पहल (National Skill Development Corporation):

1. NSDC विभिन्न सेक्टर्स जैसे – हेल्थकेयर, ओटोमोबाइल, टेक्सटाईल, आईटी, निर्माण आदि कौशल विकास कार्यक्रम संचालित करता है।
2. ये प्रशिक्षण छोटे व्यवसाय, युवाओं और बेरोजगार लोगों को नौकरी हेतु आवश्यक कौशल सिखाने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं।
3. प्रशिक्षण सत्र में प्रायोगिक शिक्षण, कक्षा ट्रेनिंग एवं नौकरी की ट्रेनिंग दी जाती है।
4. उद्योग विशेष पाठ्यक्रम विकसित करता है।
5. प्रमाण पत्र जारी करता है।
6. पब्लिक प्राइवेट पार्टनशिप (PPP) के साथ मिलकर कार्य करता है।
7. स्टार्टअप को सहायता और प्लेटफॉर्म प्रदान करती है।
8. रोजगार संबंधी सुविधाएं प्रदान करता है।
9. कौशल भारत मिशन के अन्तर्गत जन जागरूकता बढ़ाता है।

तालिका 1 : NSDC (राष्ट्रीय कौशल विकास निगम) द्वारा किए गए कार्यों के प्रकार

क्रम संख्या	कार्य	विवरण	परिणाम
1.	कौशल विकास कार्यक्रम	युवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।	रोजगार क्षमता बढ़ाना और कौशल की खाई को पाटना।
2.	उद्योग साझेदारी	निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ मिलकर कार्यक्रमों का डिजाइन और कार्यान्वयन।	उद्योग-संबंधित कौशल प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।
3.	प्रशिक्षण साझेदारों को वित्तपोषण एवं सहयोग	प्रशिक्षण संस्थानों और स्टार्टअप्स को वित्तीय सहयोग प्रदान करना।	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहुंच और गुणवत्ता का विस्तार।
4.	मानकीकरण एवं प्रमाणन	राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (NOS) का विकास।	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता बनाए रखना और मान्यता प्राप्त प्रमाणन उपलब्ध कराना।
5.	उद्यमिता एवं स्टार्टअप सहयोग	कौशल-आधारित उद्यमिता को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम।	स्वरोजगार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।
6.	अनुसंधान एवं नीतिगत सहयोग	शोध, सर्वेक्षण और नीतिगत मार्गदर्शन का संचालन।	साक्ष्य-आधारित योजना और सुधार में सहायता करना।

7.	डिजिटल एवं ऑनलाइन शिक्षण पहल	ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन पाठ्यक्रम, स्केलेबल कौशल प्रशिक्षण हेतु।	शिक्षार्थियों के लिए पहुंच और लचीलापन बढ़ाना।
8.	सेक्टर स्किल काउंसिल (SSC) सहयोग	उद्योग की आवश्यकताओं की पहचान करने और प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन करने हेतु SSCs के साथ कार्य करना।	प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बाजार की मांग के अनुरूप बनाना।

स्रोत : <https://nsdcindia.org/>

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) भारत सरकार का एक प्रमुख मंत्रालय है, जिसे 2014 में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योग-उन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि वे रोजगार योग्य बन सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। इस योजना के तहत मुख्य योजनाएं निम्नलिखित हैं—

1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) छात्रों को मुफ्त में कौशल प्रशिक्षण और प्रमाण-पत्र प्रदान करती है।
2. शिल्प प्रशिक्षण योजना (CTS) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करती है।
3. जन शिक्षण संस्थान (JSS) निरक्षरता उन्मूलन और कौशल विकास के लिए कार्य करता है।
4. राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप संवर्धन योजना (NAPS) उद्योगों में प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करती है।
5. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) हरियाणा में उद्योगों के साथ MOUs तथा छात्रों के लिए अवसर प्रदान करती है।
6. हरियाणा कौशल विकास मिशन (HSDM)⁵ – हरियाणा सरकार ने 2015 में HSDM की स्थापना की, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। HSDM ने विभिन्न उद्योगों के साथ समझौते किए हैं। जैसे—
 - उद्योग सहभागिता : NSDC उद्योगों के साथ साझेदारी करके कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन करता है।

- प्रमाणन और मानक⁶ – NSDC ने राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (NOS) और मॉडल पाठ्यक्रम विकसित किए हैं जो प्रशिक्षण की गुणवत्ता व मानक निर्धारित करते हैं।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म – NSDC ने Skill India Digital Hub (SIDH) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। जो संसाधनों की उपलब्धता तथा प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करता है।

हरियाणा कौशल विकास मिशन (HSDM)

का अवलोकन : “HSDM की स्थापना मई 2015 में हरियाणा सरकार द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना है। यह मिशन विभिन्न राजकीय विभागों के प्रयासों को एकीकृत करके कौशल विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का कार्य करता है।”

सरकार की कौशल प्रशिक्षण संबंधी मुख्य योजनाएँ (Major Skill Training Schemes of the Government)

1. **सूर्या योजना (SURYA)** – यह योजना 16–40 उम्र की आयु के युवाओं के लिए है जिसने कौशल प्रशिक्षण और पूर्व अनुभव की मान्यता (RPL) दी जाती है।
2. **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)** – इस योजना में HSDM राज्य में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करता है।

अंत HSDM ने विभिन्न उद्योग जैसे – ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए MOU⁷ Algoriquin College कनाडा मोटर वाहन और निर्माण क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए MOU किए गए हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में उद्योगों की भूमिका

1. उद्योग शिक्षा संस्थानों के साथ मिलकर पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करता है।
2. उद्योगों में काम करने का अनुभव छात्रों को दिया जाता है।
3. व्यावसायिक शिक्षा को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों से ही मुख्यधारा में शामिल किया गया है।
4. प्रशिक्षित विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं।
5. दीक्षा, स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म पर उद्योग आधारित डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।
6. उद्योगों द्वारा वित्तीय सहयोग से अनुसंधान चलाए जाते हैं।



तालिका 2 : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में उद्योगों का समन्वय

क्रम संख्या	उद्योगों की भूमिका	विवरण
1.	कौशल विकास	रोजगार योग्यता के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
2.	पाठ्यक्रम विकास	उद्योग-संबंधित पाठ्यक्रम बनाने और अद्यतन करने में मदद करते हैं।
3.	अप्रेंटिसशिप/प्रशिक्षण	इंटरनशिप और अप्रेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध कराते हैं।
4.	अनुसंधान और नवाचार	अनुप्रयुक्त अनुसंधान और सहयोगी परियोजनाओं को बढ़ावा देते हैं।

5.	अवसंरचना सहयोग	प्रयोगशालाएँ, कार्यशालाएँ और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराते हैं।
6.	रोजगार संपर्क	कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसरों की सुविधा प्रदान करते हैं।

स्रोत : <https://www.education.gov.in>

हरियाणा में कौशल विकास का विस्तार (Extension of Skill Development in Haryana)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत में शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण सुधार है। इसका उद्देश्य शिक्षा को समावेशी, व्यावसायिक एवं रोजगारोन्मुख बनाना है। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (SVSU) हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित, भारत का पहला सरकारी कौशल विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

NEP 2020 के तहत SVSU की प्रमुख पहल –

1. मल्टीपल एंट्री और एक्जिट।
2. डयूल एजुकेशन मॉडल।
3. उद्योग साझेदारी और कौशल विकास।
4. फीडर स्कूल मॉडल।
5. शोध एवं नवाचार।
6. विश्वविद्यालय में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न उपलब्धियाँ प्राप्त की। निष्कर्षतः विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय NEP 2020 के तहत कौशल शिक्षा और उच्च शिक्षा के समन्वय को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारत की शिक्षा प्रणाली में एक बहुपहल सुधार का प्रयास किया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा को व्यावसायिक और रोजगारोन्मुख बनाना है। इस नीति में उद्योगों की भूमिका को केंद्रीय स्थान दिया गया है। क्योंकि यह शिक्षा को वास्तविक विश्व की आवश्यकताओं के साथ जोड़ने में मदद करती है। उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में योगदान देता है। आने वाले समय में यह मॉडल भारत को विश्व स्तर पर कौशल हब बनाने में सक्षम होगा, जहाँ शिक्षा और उद्योग दोनों एक-दूसरे के पूरक होंगे। इस सहयोग को और भी मजबूत बनाने के लिए लगातार रणनीतिक सुधार और नीति निर्माण की आवश्यकता है।

संदर्भ

1. साधारण शिक्षण पाठन विधियाँ : सीता राम शर्मा, करन पेपर बैक्स, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2011, पृ० 190
2. शिक्षा और पाठन कला – विजेन्द्र कुमार वशिष्ठ, अर्जुन पब्लिशिंग नई दिल्ली, प्रथम संस्करण-2003, पृ० 1
3. रविन्द्रनाथ का शिक्षा दर्शन (रविन्द्र नाथ ठाकुर) अनुवादक गोपाल प्रधान, ग्रंथ शिल्पी, नई दिल्ली,

- | | |
|---|---|
| 1993 पृ० सं० 113 | 7. (https://hsdm-org-in/) |
| 4. https://www-nsdcindia-org/ | 8. https:// Nationalskillsnetwork-on/ Scaling Skill – development-in-India-episode-1 |
| 5. हरियाणा कौशल विकास मिशन (HSDM)
https://hsdm-org-in/ | 9. दैनिक भास्कर सोमवार 15 सितम्बर 2025 |
| 6. Haryana Skill Development Mission
(https://hsdm-org-in/) | 10. nep 2020-and vocational-courses-in-india/ |